पछिड़ों के आरक्षण को लेकर गठति आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी सर्वे रपिोर्ट

चर्चा में क्यों?

9 मार्च, 2023 को नकिाय चुनाव में पछिड़ों का आरक्षण तय करने के लयि गठति उप्र राज्य स्थानीय नकिाय समर्पति पछिड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदति्यनाथ को रपिोर्ट सौंप दी।

प्रमुख बदिु

- वदिति है कि नकिाय चुनाव के लयि नगर वकिास वभिाग द्वारा जारी आरक्षण सूची पर आपत्तजिताते हुए लोगों ने कोर्ट में याचकिा दाखलि की थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने बनिा आरक्षण के ही चुनाव कराने के नर्दिेश दयि थे।
- इस फैसले के खलिाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आयोग का गठन करके 31 मार्च तक ज़लिों का सर्वे कराके रपिोर्ट तैयार करने के नर्दिेश दयि थे, लेकनि यह रपिोर्ट तय समय-सीमा से करीब 22 दनि पहले ही सरकार को सौंप दी गई है। 350 पेज की इस रपिोर्ट को 2 महीने 10 दनि में तैयार कयिा गया है।
- गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 28 दसिंबर, 2022 को हाईकोर्ट के सेवानवृित्त न्यायमूर्त राम औतार सहि की अध्यक्षता में पाँचसदस्यीय आयोग का गठन कयिा था। गठन के बाद आयोग ने प्रदेश के सभी 75 ज़लिों में पछिड़ों की आबादी का सर्वे कराने के साथ ही रैपडि सर्वे में दखिाए गए पछिड़ी जातिके आँकड़ों, पूर्व में शासन द्वारा जारी आरक्षण सूची, चक्रानुक्रम प्रक्रयिा आदिका परीक्षण कयिा।
- आयोग ने ज़लि में भ्रमण के दौरान चक्रानुक्रम आरक्षण और रैपडि सर्वे प्रक्रयिा में मलिी खामयिों एवं उन्हें दूर करने के लयि सुझाए गए उपायों के बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
- आयोग की रपिोर्ट मलिने के बाद अब इसे कैबनिेट में मंज़ूरी दी जाएगी। इसके बाद रपिोर्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए उत्तर प्रदेश में नकिाय चुनाव कराने की अनुमतमिांगी जाएगी।
- आधकिारकि सूत्रों का कहना है कि आयोग की रपिोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलट-फेर होगा। नगर वकिास वभिाग ट्रपिल टेस्ट के आधार पर मेयर व अध्यक्ष की सीटों का नए सरि से आरक्षण करेगा। अनारक्षति कई सीटें ओबीसी के खाते में जा सकती हैं।
- वभिाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है कि राज्य सरकार आयोग की रपिोर्ट इसी माह सुप्रीम कोर्ट में रखने और चुनाव कराने की अनुमतमिांगेगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमतमिलिते ही मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण का काम शुरू करा दयिा जाएगा। मार्च के अंत तक सीटों के आरक्षण की अनंतमि अधसिूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तयिाँ ली जाएंगी, जसिसे इसे अंतमि रूप दयिा जा सके।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-commission-constituted-for-the-reservation-of-backward-submitted-the-survey-report-to-the-chief-minister